

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन संचालन योजना नियमावली 2015 को प्रख्यापित करने की राज्यपाल महोदय सहित स्वीकृति प्रदान करते हैं। अतः उक्त नियमावली की प्रति निम्नलिखित को संचानार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री क्लर्क (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग-4 में मुद्रित करा कर इसकी 500 प्रतियाँ कार्मिक अनुभाग-2 को तथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

4. प्रमुख सचिव, मा10 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।

5. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।

7. स्टाफ आधिकार, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

8. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

9. मण्डलाध्यक्ष, गढ़वाल एवं कौमायूँ मण्डल।

10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

11. प्रबन्धन निदेशक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक वक्क विकास निगम, देहरादून।

12. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

13. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

14. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।

15. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

आज्ञा से,

(मोहम्मद शाहिद)

सचिव।

### कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण एवं प्रोत्साहन हेतु मुख्यमन्त्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना बनाए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

मुख्यमन्त्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन संचालन योजना नियमावली-2015

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार :-

1. (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम मुख्यमन्त्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन संचालन योजना, 2015 है।

(2) यह पुराना प्रवृत्त होगी।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

परिभाषा :-

इस योजना में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

2. (क) राज्य सरकार, से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ख) विभाग, से उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अभिप्रेत है;

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, से प्रमुख सचिव/सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

अभिप्रेत है;

(घ) निदेशक, से निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ङ) जिला स्तरीय अधिकारियों से जिले में पदस्थ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) राजकीय सेवा से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जिसका वेतन राजकोष से आहरित होता हो एवं जिसकी सेवाएं संविधान के अनुच्छेद 309 से आरक्षित होती हैं।

प्रमाण पत्र की अभिप्रेमणीत प्रति संलग्न करनी होगी)

(ख) प्रार्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवासी हो। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सृजनात

4. (क) प्रार्थी अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन) का सदस्य हो।

अनुदान की पात्रता :-

अस्पृष्टों की प्रार्थना पत्र के साथ इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह इस राशि का उपयोग उत्तराखण्ड राज्य एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु ही करेगा। अस्पृष्टों के प्रार्थना पत्र में अंकित बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

(बी) मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त साक्षात्कार की तैयारी हेतु ₹ 20,000/- मात्र।

(एक) प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त - ₹ 60,000/- मात्र।

पर सकल होने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के अस्पृष्टों को निम्न प्रकार से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जायेगी।  
संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के अतिरिक्त उच्च न्यायिक सेवा एवं प्रान्तीय सिविल सेवा (न्यायिक) के विभिन्न स्तरों उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती)

संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं उच्च न्यायिक सेवा एवं प्रान्तीय सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा हेतु :-

(ख) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती)

में अंकित बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

राशि का उपयोग सिविल सेवा मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु ही करेगा। अस्पृष्टों के प्रार्थना पत्र अस्पृष्टों की प्रार्थना पत्र के साथ इस आशय के साथ घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह इस

(बी) मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त साक्षात्कार की तैयारी हेतु ₹ 25000/- मात्र।

75000/मात्र।

(एक) प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त तैयारी हेतु ₹ 0

सकल होने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के अस्पृष्टों को निम्न प्रकार से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जायेगी:-  
संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित आखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अखिलसिखित स्तर पर

3. (क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा हेतु :-

अनुदान सहायता :-

दिये जाने हेतु योजना।

लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं उच्च न्यायिक सेवा/प्रान्तीय सिविल सेवा (न्यायिक) सीधी भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अस्पृष्टों को प्रोत्साहन राशि

वार्षिक आय (अस्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) 4.50 लाख रुपये से अधिक न हो। (आय प्रमाण-पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा जारी किया गया हो, जो अधिकतम 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो)।

(घ) अल्पसंख्यक वर्ग समुदाय के अस्थियों को उपरोक्तानुसार परीक्षाओं के उत्तीर्ण होने पर प्रथम बार सफलता प्राप्त करने पर उल्लिखित राशि की 100 प्रतिशत राशि देय होगी। द्वितीय बार 50 प्रतिशत राशि ही देय होगी। उसके बाद कोई सहायता नहीं दी जायेगी।

(ङ) यदि अस्थी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा एवं उत्तराखण्ड राज्य व प्रवर अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) सीधे भारतीय सिविल सेवा (न्यायिक) सीधी भर्ती परीक्षा में संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं उच्च न्यायिक सेवा/प्रान्तीय सिविल सेवा (न्यायिक) सीधी भर्ती परीक्षा में एक ही वित्तीय वर्ष में दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता है, तो उसे एक ही योजना के अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा। यह अस्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प पर निर्भर करेगा कि वह किस योजना के तहत लाभ लेना चाहता है।

(च) जो अस्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में कार्यरत/व्यपिन है, तो उन्हें इस योजना में परीक्षा के लिए लाभ दिया जायेगा। किन्तु उनकी एवं उनके परिवार की वार्षिक आय सभी स्त्रियों से रु० 4.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(छ) अस्थी के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी संज्ञेय वाद लभित न हो एवं न्यायालय से दण्डित न हो।

### अनुदान स्वीकृति की शर्त :-

5. उपरोक्त राशि के लिये निम्नलिखित बिन्दुओं की पूर्ति करने पर अस्थी द्वारा सम्बन्धित जिले के जिला स्तरीय अधिकारी को आवेदन पत्र दिया जायेगा। जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रविष्टियाँ हेतु एक पंजिका का संधारण किया जायेगा। पात्रता की निम्न जाँच के उपरान्त निदेशक के अनुमोदनापरांत सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी की जायेगी।

(क) प्रार्थी अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन) का सदस्य हो।

(ख) प्रार्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल अथवा स्थायी निवासी हो। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सुसंगत)

(ग) अस्थी द्वारा भारतीय सिविल सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

(ग) अस्थी द्वारा भारतीय सिविल सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त तथा उत्तराखण्ड राज्य व प्रवर अधीनस्थ सेवा एवं उच्च न्यायिक सेवा/प्रान्तीय सिविल सेवा (न्यायिक) सीधी भर्ती परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने एवं साक्षात्कार में सम्मिलित होने का प्रमाण पत्र पेश करना होगा।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना (द्वितीय भाग) के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के अध्येष्टियों को निम्नलिखित राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं एवं प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहन के रूप में राशि निम्नानुसार प्रदान की जायेगी:-

संस्थान का नाम एवं देय अनुदान की राशि का विवरण -

1. समूह (क)-इसके अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थान/परीक्षाएँ सम्मिलित हैं :-

- (एक) IITs (Indian Institute of Technology)  
(दो) IIMs (Indian Institute of Management)  
उक्त संस्थानों/परीक्षाओं की प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अध्येष्टी को देय अनुदान की राशि - रु 60,000 मात्र।

समूह (ख)-इसके अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थान/परीक्षाएँ सम्मिलित हैं :-

- (एक) AIIMS (All India Institute of Medical Sciences) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  
(दो) IIS (Indian Institute of Science) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर  
(तीन) IISAR (Indian Institute of Science and Applied Research) भारतीय विज्ञान एवं प्रायोगिक अनुसंधान संस्थान, कोलकाता एवं बंगलौर  
(चार) MCI (Medical Council of India) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज  
(पांच) AICTE (All India Council for Technical Education) द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी संस्थान एवं (NITS) राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान  
(छः) BCI (Bar Council of India) द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों एवं CLAT (Common Law Admission Test) हेतु

उपरोक्त संस्थानों/परीक्षाओं में प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अध्येष्टी को देय अनुदान की राशि रु 50,000 मात्र।

2. उक्त समूह (क) अथवा (ख) के अन्तर्गत निर्धारित संस्थानों की परीक्षाओं में से किसी दो या दो से अधिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की दशा में सम्बन्धित अध्येष्टी को केवल एक ही परीक्षा के सापेक्ष अनुदान राशि देय होगी, जो भी उसके लिए अधिक लाभकारी हो।

3. इस योजना के अन्तर्गत प्राविधानित अनुदान राशि अध्येष्टी द्वारा उक्त संस्थानों की सफल होने का मूल आवेदन पत्र/प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

4. इस योजना के अन्तर्गत अनुदान की पात्रता, अनुदान स्वीकृति की शर्त, आवेदन की समय सीमा, योजना की मॉनीटरिंग एवं बजट आवंटन तथा नियमों का विनिर्णय उसी प्रकार होगा जैसाकि इस नियमावली के भाग-प्रथम में नियत है।

(मोहम्मद शाहिद)  
सचिव।